ईएसआई मेडिकल कॉलेज से संबंधित मुख्य समाचार पेज 8 पर देखें

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा का ज्ञापन

माननीय डायरेक्टर जनरल, ई एस आई सी, दिनांक : 06.11.2023
पंचदीप भवन, इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002

विषय: ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज, फ़रीदाबाद के पुरुष गार्ड्स द्वारा हमारी महिला कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला: मेडिकल कॉलेज डीन का अत्यंत आपत्तिजनक व तानाशाहीपूर्ण बर्ताव

सन्दर्भ: मज़दूर अशोक कुमार, आईपी; एचआर 01.0000068654 के इलाज में लापरवाही

आदरणीय महोदय,

अशोक कुमार, सुपुत्र श्री गंगादयाल प्रसाद, आई पी नंबर एचआर 01.0000068654, 10 जून, 2023 से बहुत तकलीफ़देह, कमर दर्द से पीड़ित हैं. वे तभी से, अनेक बार अपनी दिहाड़ी गंवाकर ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज, फ़रीदाबाद, इलाज के लिए आते रहे. डॉक्टर हर बार उन्हें दर्द निवारक इंजेक्शन और गोलियां देकर घर भेजते रहे. कोई गंभीर जांच या इलाज करने की जहमत नहीं उठाई उनका दर्द बढ़ता गया और 30 अक्टूबर को असहनीय हो गया. वे दर्द से तड़पने लगे. तीन लोग उन्हें किसी तरह, मेडिकल कॉलेज, फ़रीदाबाद लेकर आए. उस दिन भी, जब वे स्ट्रेचर पर लेट भी नहीं पा रहे थे, और दर्द से चीख रहे थे, उन्हें पेन किलर इंजेक्शन देकर टरकाया जाने लगा, तब हमारे संगठन ने उसका विरोध किया और उन्हें भर्ती करने का अनुरोध किया. उन्हें भर्ती कर लिया गया. हालांकि उनके बेड की एक टांग टूटी हुई है, जो ईंटों पर टिकी हुई है. उसी दिन, 30 अक्टूबर को डॉ. बृजेश ने कहा, कि दर्द गंभीर प्रकृति का मालूम पड़ता है. इनका एम आर आई टेस्ट होना ज़रूरी है. हमने सम्बंधित स्टाफ से बार-बार अनुरोध किया कि उनका एम आर आई टेस्ट किया जाए. अशोक कुमार, लगातार दर्द से कराह रहे थे और सो भी नहीं पा रहे थे. 2 नवम्बर तक भी, जब ये टेस्ट नहीं हुआ, तो हमने ई मेल द्वारा, डॉ. निशा रजनी तथा डीन साहब को लिखित शिकायत की. उसके बाद भी 3 नवम्बर तक उनका टेस्ट नहीं हुआ और अशोक कुमार दिन से सो नहीं पाए थे.

अशोक कुमार की बिगड़ती हालत और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ़ व प्रशासन के संवेदनहीन तथा गैरजिम्मेदार रवैय्ये से, हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी और आक्रोशित थे यह तय हुआ कि डीन साहब को ज्ञापन दिया जाएगा. 3 नवम्बर को हमारे 35 कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के गेट न.1 के बाहर इकट्ठे हुए और अनुशासित मोर्चे के साथ, डीन कार्यालय की ओर बढ़े. यह तय हुआ था कि जहाँ भी रोका जाएगा, हम वहीं रुक जाएंगे और 2-3 साथी ज्ञापन देने जाएँगे, या कोई ज़िम्मेदारी अधिकारी वहीं आकर ज्ञापन स्वीकार कर लेंगे. डी सी कार्यालय, फ़रीदाबाद पर भी बिलकुल इसी तरह विरोध प्रदर्शन करने का नियम है हमारे अनुशासित मोर्चे को ओ पी डी के सामने वाली सड़क तक पहुँचने से पहले, किसी ने नहीं रोका. वहां अचानक रोक लिया गया और एच ओ डी. सुरक्षा, श्री सत्यानन्द पांडे तथा सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति ने, हमें गालियां देते हुए, जमा हो गए गार्ड्स को, हमारे ऊपर लाठियों से हमला करने को उकसाया वे खुद भी डंडे लेकर, कार्यकर्ताओं को पीटने लगे. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरता की इन्तेहा यह थी कि पुरुष गार्ड्स हमारी महिला कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटने लगे, उनके बाल खीचने लगे, थप्पड़-घूंसे मारने लगे, हमारे अध्यक्ष, कॉमरेड नरेश को, तीन गार्ड्स ने उठाकर, ज़मीन पर पटका, बुरी तरह पीटा और घसीटा, कई मोबाइल, माइक आदि तोड़ दिए गए एक साथी शेरसिंह को बूटों से ठोकरें मारीं, वे आज भी चल नहीं पा रहे साथियों को, जिनमें महिलाऐं है, गंभीर चोट लगी है. उनका मेडिकल परीक्षण, इलाज तथा मेडिको लीगल रिपोर्ट, स्थानीय बी के हॉस्पिटल में हुआ है सारे दस्तावेज तथा विडियो हमारे पास सुरक्षित हैं. हमें खदेड़कर गेट से बाहर कर दिया गया.

उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की पूरी जानकारी ली. हमारा ज्ञापन पढ़ा और कहा, कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, आप 4-3 लोग जाकर ज्ञापन दे आइये हम साथी ज्ञापन देने डीन के दफ्तर पहुंचे उनकी सेक्रेटरी ने ज्ञापन,डीन साहब के पास भेजा और उनकी अनुमति मिलने पर ही, हम लोग उनके चैम्बर में प्रवेश किए उसी वक्त सुरक्षा इंचार्ज सत्यानंद पांडे ने उन्हें एकदम झूठ और बेबुनियाद खबर दी कि हमने डाक्टरों पर हमला किया है, जबकि कोई भी डॉक्टर वहां मौका-ए-वारदात पर मौजूद नहीं था. डीन साहब ने हमसे कोई सवाल नहीं किया. घटना की जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की, और आपा खो बैठे. उन्होंने हमारा ज्ञापन फाड़कर फेंक दिया. इतना ही नहीं, हम ही क्या, उनका स्टाफ़ भी यकीन नहीं कर पाया, जब वे हमारे संगठन के अध्यक्ष को गले से पकड़कर बाहर तक धकेलते ले गए इतनी ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठे व्यक्ति का इतना घटिया, गली छाप गुंडों जैसा, घोर आपत्तिजनक एक दम खांटी अपराधी जैसा आचरण देखकर, हम लोग सन्न रह गए इतने तीखे उकसावे और भड़काने के बावजूद, हम लोगों ने संयम और मर्यादा नहीं तोड़ी. बाद में पुलिस मौके पर आई. सारी जानकारी ली. 4 अक्तूबर को लिखित पुलिस शिकायत भी की जा चुकी है.

हमारी मांगें:

1) 3 नवंबर को हमारे कार्यकर्ताओं पर हुए जानलेवा हमले की स्वतन्त्र जांच कराई जाए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए.

2) पुरुष गार्ड्स द्वारा, महिला कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला, उनके बाल खींचने, घसीटने पीटने की वारदात एक गंभीर अपराध है ऐसे अपराधियों को तुरंत नौकरी से बरखास्त किया जाए उनके विरुद्ध आपका संस्थान भी अपराधिक मुकदमा दर्ज करें.

3) मेडिकल कॉलेज के डीन, श्री असीम दास का बर्ताव बहुत ही आपत्तिजनक, लज्जास्पद तथा आपराधिक है. उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए.

4) फ़रीदाबाद में पंजीकृत मज़दूरों की कुल संख्या के अनुरूप, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जाए मेडिकल कॉलेज में. बेड, डॉक्टर, सहायक स्टाफ, टेस्ट सुविधाओं, दवाईयों आदि का नितांत अभाव है. दूसरी ओर, निगम का कुल जमाकोष 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है. कुल 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले, मज़दूर इतनी विकट कंगाली में जीवन जीते हैं कि वे किसी भी निजी संस्थान में इलाज नहीं करा सकते. वे मर जाएंगे मर रहे हैं.

5)फ़रीदाबाद में 80प्रतिशत कारखानेदार, मज़दूरों से ई एस आई सी की कटौती कर डकार जाते हैं, उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करते. यह जानकारी हमें आधिकारिक स्रोत से मिली है. निगम ने, इंस्पेक्टर की भर्ती बंद कर दी है. साथ ही कारखानेदारों की ये समझ बन गई है, कि मज़दूरों के, ई एस आई कार्ड बनाने की ही ज़रूरत नहीं और बन भी गए हैं, तो उनके वेतन से काटे गए पैसे को निगम में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है. यह विकट स्थिति कभी भी विस्फोटक बन सकती है. समय रहते इस मामले में समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए.

मंत्री जी, मेलों से नहीं रोजगार से बढ़ेगा हैप्पीनेस इंडेक्स

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। सूरजकुंड दिवाली मेले का उद्घाटन करने आए प्रदेश के पर्यटन एवं शिक्षामंत्री कंवरपाल गूजर ने ऐलान किया कि प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए सूरजकुंड में हर साल तीन मेले लगाएंगे। सत्ता का सुख भोग रहे कंवरपाल गूजर भूल गए कि जनता को खुशी मेले लगाने से नहीं बल्कि महंगाई कम करने, रोजगार देने और सामाजिक सुरक्षा देने से मिलती है। हैप्पीनेस इंडेक्स किन मानकों पर तय होता है अगर शिक्षामंत्री को यह पता होता तो संभवता वो इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करते, लेकिन संघ-भाजपा की रीति-नीति कि काम नहीं करो, बस काम का ढिंढोरा पीटो की तर्ज पर वह भी अपने गाल बजा कर चले गए।

मोदी-शाह के 'कुशल नेतृत्व' में भारत अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची में 150 देशों में बीते वर्ष से दस पावदान लुढ़क कर 146 वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2020 के भारत के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा 10 में 3.36 अंक के साथ सत्रहवें स्थान पर था। यह स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। सावन के अंधे को सब हरा दीखता है कहावत को चरितार्थ कर रहे शिक्षा मंत्री को महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, लैंगिक भेदभाव-उत्पीड़न और सांस्कृतिक आतंकवाद जैसी बुराइयां नजर ही नहीं आ रहीं, तभी तो उन्हें लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई लुटा कर मेला लगाओ और ढिंढोरा पीटो कि जनता खुश हो रही है।

हैप्पीनेस इंडेक्स का पहला कारक प्रति व्यक्ति आय है। ऑक्सफेम इंडिया के जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार दस प्रतिशत से कम नागिरकों के पास देश की 62 फीसदी से ज्यादा संपत्ति है। जबकि पचास फीसदी जनता के बीच महज तीन प्रतिशत संपत्ति का बंटवारा है। जिस देश में आबादी का लगभग साठ फीसदी हिस्सा यानी अस्सी करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए मुफ्त के सरकारी राशन की जरूरत हो दूसरी ओर अरब पतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो जाए वहां कौन खुश है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यमुना नगर के रेत एवं बजरी माफिया से राजनेता बने कंवरपाल कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, बड़ा मकान है लेकिन खुशी नहीं है इसलिए मेले लगाए जाने चाहिए, समझा जा सकता है कि वो जनता के किस तबके की हैप्पीनेस की बात कर रहे थे।

एक अन्य कारक औसत आयु है जो बीते 25 वर्षों में हरियाणा में बढ़कर 67 वर्ष हो गई थी लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण बीते दो तीन वर्षों में प्रदेश में औसत आयु में एक साल की कमी हुई है। बिजली, पेयजल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी झेल रही जनता प्रदूषण की मार से भी जूझ रही है लेकिन कंवरपाल की नजर में सब चंगा है।

तीसरा कारक सामाजिक सौहार्द है जो कि खट्टर सरकार में छिन्नभिन्न हो चुका है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सरकार जातियों के बीच नफरत फैलाने वालों को समर्थन दे रही है। समाज में असुरक्षा और भय का माहौल फैला कर सत्ता पर कब्जा रखने का संघ-भाजपा का खेल जारी है, और मंत्री कंवरपाल इसे हैप्पीनेस इंडेक्स के पर्दे में छिपा रहे हैं।

चौथा कारक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इसी से समझी जा सकती है कि टीबी के मरीजों को महीनों से दवाएं नहीं मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में आधारभूत दवाओं का अभाव रहता है। यूएचसी, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं न पैरा मेडिकल स्टाफ। सीएम खट्टर द्वारा घोषणा किए गए मेडिकल कॉलेज भी हवा हवाई ही हैं। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज इसका उदाहरण है जो आज तक ठीक से नहीं चल सका और उस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल की तलवार लटक रही है।

पांचवां कारक सामाजिक सुरक्षा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली खट्टर सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां ही हैं। महिला जूनियर एथलेटिक कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी राज्यमंत्री संदीप सिंह को खट्टर ने पूरा संरक्षण दिया और पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उसे ही निलंबित कर दिया। जूनियर खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोपी केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण सिंह आज भी खुलेआम घूम रहा है जबकि दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवानों से सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासन ने जमकर अभद्रता की। हक की मांग कर रहे किसानों को कुचलने का पूरी तरह प्रयास किया गया। नौकरी मांगने वाले छात्र-छात्राओं पर इसी खट्टर सरकार में लाठियां चलवाई गईं। मंत्री कंवरपाल के हैप्पीनेस इंडेक्स में यह घटनाएं नहीं आतीं क्योंकि उनकी सरकार में 'रामराज' है।

सबसे महत्वपूर्ण कारक भ्रष्टाचार है। खट्टर की बीते नौ सालों की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। इतना जरूर हुआ है कि रिश्वत के दाम दोगुने चौगुने हो गए। आईएएस जैसे आला अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार की सीमाएं इस कदर उलांघ दीं कि खट्टर सरकार को न चाहते हुए भी उनकी गिरफ्तारियां करनी पड़ीं। कुछ एक आईएस ऑफिसर ऐसे हैं जो आकाओं-मंत्रियों को चढ़ावे की आड़ में बचते घूम रहे हैं। समझा जा सकता है कि जब आला अफसर भ्रष्ट होंगे तो निचले स्तर के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने से कौन रोक सकेगा। परिवार पहचान पत्र हो, राशन कार्ड बनवाना या पेंशन बंधवानी हो बिना मुट्ठी गर्म किए आम जनता का काम कहीं नहीं होता।

हैप्पीनेस सिर्फ कहने से या मेला लगाने से नहीं आ जाती। जब आम जनता के पास रोगजार होगा, परिवार को जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद बचत होगी तभी आम आदमी मेला देखने जाएगा, खाली पेट और खाली जेब मेले नहीं सूझते बल्कि निकम्मी सरकार के प्रति रोष ही पनपता है।

दुकानदारों की तो हैप्पीनेस छिन गई

दिवाली मेले में बड़ी कमाई और हजारों की भीड़ का सुनहरा ख्वाब दिखा कर सूरजकुंड मेले में बुलाए गए दुकानदारों की खुशी ग्राहक न आने से काफूर गई है। मेला प्रबंधन और प्रशासन पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगाते हुए इन दुकानदारों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। इन दुकानदारों का कहना था कि अधिकारियों ने बताया था कि मेले में प्रतिदिन कम से कम पंद्रह हजार लोग आएंगे वीक एंड पर तो यह संख्या दो गुनी हो सकती है लेकिन इसके उलट पांच दिन बीत गए ग्राहक दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मेले में जितने स्टॉल लगे हैं उतने तो दर्शक भी नहीं आ रहे ग्राहक कहां से बनेंगे। कुछ युवा आते हैं तो वो खरीदारी करने नहीं बल्कि चौपाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने और मौज मस्ती करने। दुकानदारों का कहना है कि स्टॉल का किराया छोड़ भी दिया जाए तो सामान लाने में जितना भाड़ा खर्च हुआ वो भी नहीं निकल पाया है। रोजाना का खर्च अलग से हो रहा है ऊपर से मेला प्रबंधन ने तीस रुपये का टिकट लगा रखा है जिससे भी लोग परिवार के साथ आने से कतरा रहे हैं। ग्राहक नहीं आने के कारण अधिकतर दुकानदार आठवें दिन ही सामान समेट का चलते बने।

स्थानीय शहरी निकाय मुख्यालय .... पेज एक का शेष

यह सुविधा रवि शर्मा को नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह 2005 में ही नियमित सहायक अभियंता बने थे। नियमानुसार उनको पहली एसीपी नवंबर 2010 में मिलनी चाहिए थी। अवर सचिव सूबे सिंह ने रवि शर्मा की दूसरी एसीपी 2011 और तीसरी एसीपी मार्च 2017 को जारी कर दी। नियमानुसार रवि शर्मा को पहली एसीपी नवंबर 2010 दूसरी एसीपी नवंबर 2016 और तीसरी एसीपी नवंबर 2022 में जारी की जानी चाहिए थी।

बताते चलें कि रवि शर्मा अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो गए थे इस आधार पर उन्हें तीसरी एसीपी के फायदे भी नहीं मिलने चाहिए थे। स्थानीय निकाय विभाग के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सूबे सिंह कर्मचारियों को ये सुविधाएं अच्छे होटल में भोजन, महंगी शराब और चंद लाख रुपये सुविधा शुल्क के एवज में उपलब्ध कराता है। जो कर्मचारी ऐसा नहीं करते उनकी फाइल या तो लटका दी जाती है या फिर उन्हें नियमानुसार एक सितंबर 2009 से ही नए एसीपी का लाभ दिया जाता। मुट्ठी गर्म होने पर नियम भी किनारे कर दिए जाते हैं जैसे रवि कुमार शर्मा के मामले में किया गया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि लाभ लेने वाले कर्मचारी अपने एसीपी संबंधित कागज खुद ही टाइप करा कर लाते हैं और सूबे सिंह सेवा व सुविधा पाने के बाद उन पर हस्ताक्षर कर मुहर लगा देते हैं। खट्टर बिना खर्ची बिना पर्ची के काम होने के हवाहवाई दावे करते रहे और उनके ही कार्यकाल में नगर निगम में दो सौ करोड़ का घोटाला हो गया। घोटालेबाज अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस वाले खट्टर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर सके, यहां तक कि भ्रष्टाचार नगर निगम से लेकर स्थानीय शहरी निकाय विभाग के सचिवालय तक पहुंच गया। नौकरशाही की बैसाखी पर चलने वाले खट्टर में इतनी ताकत नहीं है कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सकें, बस वो तो बड़े-बड़े जुमले फेक कर छवि चमकाने में जुटे हैं।